दृष्टि
The Vision

करेंट अफेयर्स मध्य प्रदेश

अक्तूबर (संग्रह)

2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोनः 8750187501

ई-मेलः online@groupdrishti.com

अनुक्रम

मध्य प्रदेश **5**

- राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 5
- भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय केंद्र 5
- उज्जैन में तारामंडल परिसर में विज्ञान केंद्र का भूमिपूजन 5
- पचमढ़ी में मैराथन का तृतीय संस्करण आयोजित 6
- प्रदेश के दो इंजीनियरिंग महाविद्यालयों को मिला एनबीए एक्रिडेशन 7
- हिन्दी सेवा सम्मान 7
- अंतर्राज्यीय लघु फिल्म महोत्सव 7
- प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप ने विश्व रिकॉर्ड के साथ विश्व चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक 8
- एन.सी.पी.सी.आर. द्वारा 'बच्चों के लिये समर्पण' कार्यक्रम 8
- 'स्वामित्व योजना' 9
- मध्य प्रदेश में बड़ी ग्राम पंचायतों में खुलेंगे उप-लोक सेवा केंद्र 9
- एकमुश्त समझौता योजना 10

दृष्टि The Vision

नोट :

- पुलिस परिवार के बच्चों को रोज़गारोन्मुखी पाठ्यक्रम के लिये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर 10
- भोपाल के वैज्ञानिक ने देश का पहला प्लास्टिक फ्री सैनिटरी नैपकिन बनाया 11
- ग्वालियर में 'अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक न्यास' के गठन की स्वीकृति 11
- अपशिष्ट प्रबंधन एवं निष्पादन के लिये एम.ओ.यू. 12
- भोपाल हाट में विंध्यावैली के दस स्वदेशी प्रोडक्ट लॉन्च 13
- 'गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान' 13
- 'जायका' का शुभारंभ 14
- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश 14
- लाडली लक्ष्मी उत्सव 14
- यूथ नेशनल सैलिंग चैंपियनशिप-2021 15
- एमएसएमई की नई पॉलिसी 15
- हाइब्रिड स्विचगियर मॉड्यूल तकनीक 16
- राष्ट्रीय मेरिट पुरस्कार 2018 17
- विद्युत दरों पर सब्सिडी 17
- 'मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार' योजना 18
- 'खादी शो' 19

नोट :

- ‘जीव दया पुरस्कार’ 19
- सोन चिरैया आजीविका उत्सव, 2021 का शुभारंभ 20
- डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स कमेटी 20
- शासकीय सेवकों के डी.ए. में 8% की वृद्धि 21
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन लॉजिस्टिक्स 21
- प्रथम हॉकी इंडिया जूनियर बालक इंटर अकादमी नेशनल हॉकी चैंपियनशिप, 2021 22
- स्टैंडिंग कमेटी 22
- दुष्यंत कुमार स्मृति पांडुलिपि संग्रहालय द्वारा वार्षिक अलंकरण की घोषणा 22
- एम्स भोपाल और आईआईएसईआर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर 23
- राष्ट्रीय सीनियर कैनो स्प्रिंट कयाकिंग-कैनोइंग चैंपियनशिप, 2021 23
- मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 24

मध्य प्रदेश

राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान

चर्चा में क्यों ?

- 30 सितंबर, 2021 को मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव (संस्कृति और पर्यटन) शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि अखिल विश्व गायत्री परिवार का वर्ष 2019 और भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान का वर्ष 2020 के लिये 'राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान' हेतु चयन किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- दोनों संगठनों को ये पुरस्कार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर, 2021 को रविंद्र भवन में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान समारोह में प्रदान किये जाएंगे।
- समारोह में हरिद्वार में स्थापित अखिल विश्व गायत्री परिवार और यमगरवाड़ी (उस्मानाबाद) में स्थापित भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान को 10 लाख रुपए की आय कर मुक्त सम्मान राशि, सम्मान पटिका, शॉल और श्रीफल प्रदान किये जाएंगे।
- उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्मृति में गांधी विचार दर्शन के अनुरूप समाज में रचनात्मक पहल, सांप्रदायिक सद्भाव एवं सामाजिक समरसता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 1995 में यह सम्मान स्थापित किया था।
- राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किसी भी संस्था को प्रदान किया जाने वाला मध्य प्रदेश का बड़ा सम्मान है।

भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय केंद्र

चर्चा में क्यों ?

- 30 सितंबर, 2021 को मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जयंत सोनवलकर ने बताया कि भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय के छात्र सुविधा केंद्र अब प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों में खुलेंगे।

प्रमुख बिंदु

- कुलपति सोनवलकर ने कहा कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद और बड़वानी में स्थित 11 क्षेत्रीय केंद्रों के साथ, विश्वविद्यालय ने इस वर्ष 2 लाख विद्यार्थियों के प्रवेश का लक्ष्य रखा है।
- उन्होंने कहा कि छात्रों को भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अवगत कराने के लिये रामचरित मानस से सामाजिक विकास में डिप्लोमा शुरू किया गया है। छात्रों के लिये ऑडियो-वीडियो व्याख्यान सेवा भोज वाणी तथा भोज दर्शन भी आयोजित किये जा रहे हैं।
- विश्वविद्यालय की ई-सामग्री और स्व-शिक्षण सामग्री भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जो दूरस्थ शिक्षा वाले कॉलेज और पारंपरिक विश्वविद्यालय के छात्रों के लिये ओपन सोर्स में भी उपलब्ध हैं।

उज्जैन में तारामंडल परिसर में विज्ञान केंद्र का भूमिपूजन

चर्चा में क्यों ?

- 30 सितंबर, 2021 को कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उज्जैन में तारामंडल परिसर में विज्ञान केंद्र का भूमिपूजन किया तथा प्रदर्शनी की विवरणिका का विमोचन भी किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद कलकत्ता तथा संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की योजना के अंतर्गत इस विज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है। यह केंद्र पाँच एकड़ क्षेत्र में लगभग 16.70 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होगा।
- इस केंद्र के स्थापित होने से शिक्षा से जुड़े लोग लाभान्वित तथा जन-समुदाय की विज्ञान में रुचि बढ़ेगी। विज्ञान के अनसुलझे रहस्यों के बारे में विद्यार्थी जान सकेंगे। विज्ञान केंद्र में आधुनिक उपकरण लगेंगे। इसे आगे चलकर काल गणना के बड़े केंद्र के रूप में भी विकसित किया जाएगा। इस विज्ञान केंद्र की मुख्य विशेषताएँ निम्न हैं-
- इसे इनोवेशन हब बनाया जाएगा तथा इसमें कई हाईटेक उपकरण व गैजेट्स लगेंगे।
- इनोवेशन हब में उपकरणों पर विद्यार्थी शोध कर सकेंगे।
- विद्यार्थियों को लैब में मृदा, जल एवं खाद्य पदार्थ के नमूनों का परीक्षण करना भी सिखाया जाएगा।
- विज्ञान केंद्र में 14 करोड़ में थ्रीडी स्टूडियो भी बनेगा, जिसमें विज्ञान की दृष्टि से सबसे उन्नत उपकरण लगाए जाएंगे।
- इस केंद्र की स्थापना के लिये राज्य शासन 8.65 करोड़ रुपए देगी तथा शेष राशि 6.55 करोड़ रुपए राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता और संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से दी जाएगी।

पचमढ़ी में मैराथन का तृतीय संस्करण आयोजित

चर्चा में क्यों?

- 3 अक्टूबर, 2021 को मध्य प्रदेश के खूबसूरत हिल स्टेशन पचमढ़ी के नैसर्गिक सौंदर्य और प्राकृतिक वातावरण से पर्यटकों को रू-ब-रू कराने तथा पर्यटन के लिये अधिक से अधिक सैलानियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा 'पचमढ़ी मैराथन' का तृतीय संस्करण आयोजित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक एस. विश्वनाथन ने कहा कि मैराथन के आयोजन से प्रदेश में स्वास्थ्य पर्यटन (वेलनेस टूरिज्म) एवं एक्टिव हॉलीडेज कांसेप्ट को बढ़ावा देने का एक सार्थक प्रयास किया जा रहा है।
- पचमढ़ी प्रदेश का नंबर वन टूरिज्म स्पॉट है। यहाँ साल भर सभी मौसम में चाहे सर्दी हो या बरसात, देश के कोने-कोने से सैलानी आते हैं और प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाते हैं।
- विश्वनाथन ने कहा कि पचमढ़ी में प्रोफेशनल मैराथन आयोजित किये जाने की कार्य-योजना तैयार की जा रही है।
- इस मैराथन को तीन श्रेणियों 5 किमी., 10 किमी. और 21 किमी. में आयोजित किया गया। इन श्रेणियों को फैमिली फन रन, एंड्योरेंस रन और धूपगढ़ पहाड़ी रन नाम दिया गया।
- टूरिज्म बोर्ड ने मैराथन में भाग लेने वाले सभी धावकों को टी-शर्ट, आरएफआईडी टाइमिंग चिप, रूट सपोर्ट, फिनिशर्स मेडल और ई-सर्टिफिकेट प्रदान किये। साथ ही प्रतियोगिता के शीर्ष तीन धावकों को अतिथियों ने ट्रॉफी और दो रात्रि और तीन दिवस के फ्री स्टे वाउचर प्रदान किये।
- उल्लेखनीय है कि मैराथन का पहला संस्करण 22 जुलाई, 2018 को आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 800 पर्यटकों ने भाग लिया। प्रथम संस्करण की अपार सफलता के बाद इस मैराथन को मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में प्रतिवर्ष आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
- इसका दूसरा संस्करण वर्ष 2019 में 21 जुलाई को आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 800-1000 पर्यटकों ने हिस्सा लिया। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत वर्ष 2020 में इस मैराथन आयोजन नहीं हो सका था।
- मैराथन का तीसरा संस्करण में कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए समस्त बचाव और सुरक्षा निर्देशों का पालन कर सीमित प्रतिभागियों के साथ आयोजित की गई। भाग लेने वाले सभी पर्यटकों को पूर्ण रूप से कोविड वैक्सीनेटेड होना और कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य था।

नोट :

प्रदेश के दो इंजीनियरिंग महाविद्यालयों को मिला एनबीए एक्रिडेशन

चर्चा में क्यों?

- 01 अक्टूबर, 2021 को मध्य प्रदेश के दो इंजीनियरिंग महाविद्यालयों को नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रिडेशन, नई दिल्ली से चार पाठयक्रमों के लिये वर्ष 2022-23 तक एक्रिडेशन मिला है।

प्रमुख बिंदु

- रीवा एवं उज्जैन के शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में मध्य प्रदेश के छात्र-छात्राओं को उच्च कोटि की तकनीकी शिक्षा मिलने की प्रामाणिकता प्राप्त हो गई है।
- उल्लेखनीय है कि नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रिडेशन से हाल ही में उज्जैन इंजीनियरिंग महाविद्यालय के मैकेनिकल पाठयक्रम और रीवा इंजीनियरिंग महाविद्यालय के तीन सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पाठयक्रम को एक्रिडेशन प्राप्त हुआ है।
- तकनीकी शिक्षा मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने जानकारी दी कि रीवा एवं उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेजों के इन पाठ्यक्रमों की शिक्षा को अब राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों, जैसे- आईआईटी/एनआईटी के समकक्ष माना जाएगा।
- उन्होंने बताया कि नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रिडेशन की आठ सदस्यीय टीम द्वारा इन महाविद्यालयों की ऑफलाइन एवं ऑनलाइन विजिट कर संस्था के संपूर्ण संसाधनों, प्रयोगशालाओं, प्राध्यापकों की गुणवत्ता, पूर्व और वर्तमान छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता तथा फीडबैक की गहन जाँच करते हुए इन संस्थानों को प्रामाणिकता प्रदान की गई है।
- सिंधिया ने कहा कि इससे इन पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को देश के प्रतिष्ठित कंपनियों में प्लेसमेंट मिलने की संभावना प्रबल हो गई है। इस एक्रिडेशन से दोनों महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली से प्राप्त होने वाले अनुदानों और सुविधाओं में वृद्धि होगी।

हिन्दी सेवा सम्मान

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल द्वारा बीएचईएल के कार्यपालक निदेशक एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष सी. आनंदा को हिन्दीत्तर भाषी हिन्दी सेवा सम्मान-2021 से नवाज़ा गया।

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का प्रतिष्ठित सम्मान हिन्दीत्तर भाषी हिन्दी सेवा सम्मान-2021 का आयोजन हिन्दी भवन परिसर श्यामला हिल्स में किया गया।
- उल्लेखनीय है कि सी. आनंदा ने कन्नड़भाषी तथा तकनीकी क्षेत्र से जुड़े होने के बावजूद हिन्दी के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल की है।
- उन्होंने राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है। साथ ही, तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग, डिजिटल रूप में हिन्दी के प्रयोग पर विशेष ज़ोर दिया है।

अंतर्राज्यीय लघु फिल्म महोत्सव

चर्चा में क्यों?

- 4 अक्टूबर, 2021 को ग्वालियर में भारतीय चित्र साधना के तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय अंतर्राज्यीय लघु फिल्म महोत्सव (Inter-State Short Film Festival) कई प्रशंसित लघु फिल्मों की स्क्रीनिंग के साथ संपन्न हुआ।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- समापन समारोह ग्वालियर के सिटी सेंटर स्थित भारतीय पर्यटन प्रबंधन संस्थान में आयोजित किया गया था।
- इस दोदिवसीय उत्सव के विषयों में भारत का स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता के 75 वर्ष, अनलॉक, भारत के स्थानीय, संस्कृति और मूल्यों के लिये मुखर, नवाचार, परिवार, पर्यावरण और ऊर्जा एवं शिक्षा शामिल थे।
- महोत्सव में कन्या भ्रूण हत्या विषय पर आधारित लघु फिल्म 'धुक तारा' को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया।
- इस अवसर पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहालिनी ने कहा कि लिंग आधारित चयनात्मक उन्मूलन की रोकथाम सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि अजन्मी लड़कियों का चयनात्मक उन्मूलन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर है।
- उल्लेखनीय है कि भारतीय चित्र साधना उन फिल्मों को प्रोत्साहित करती है, जो कालातीत दर्शन, भारतीय मूल्यों और आधुनिक विकास के साथ भारतीय समाज की प्रगति को बढ़ावा देती हैं। ऐसी फिल्मों और फिल्म निर्माताओं की सुविधा तथा प्रचार के लिये 2016 से यह भारत के विभिन्न शहरों में चित्र भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कर रही है।

प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप ने विश्व रिकॉर्ड के साथ विश्व चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक

चर्चा में क्यों?

- 5 अक्टूबर, 2021 को मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने लीमा (पेरू) में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप के 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन (पुरुष) वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश को स्वर्ण पदक दिलाया। उन्होंने फाइनल में 463.4 अंकों के साथ यह उपलब्धि हासिल की।

प्रमुख बिंदु

- इसके साथ ही ऐश्वर्य ने जूनियर लेवल पर नया विश्व रिकॉर्ड भी स्थापित कर दिया। इससे पहले यह विश्व रिकॉर्ड चेक गणराज्य के फिलिप नेपेजशल के नाम था, जो उन्होंने 19 नवंबर, 2019 को 462.9 अंकों के साथ चीन में बनाया था।
- फ्राँस के लुकास बर्नार्ड डेनिस क्रीज्स 456.5 अंकों के साथ दूसरे, जबकि अमेरिका के गेविन रेमंड ली बार्निक 446.6 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे।
- टोक्यो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके ऐश्वर्य ने क्वालीफिकेशन राउंड में विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर 1185 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया था।
- ऐश्वर्य ने नीलिंग में 397, प्रोन में 398 और स्टेंडिंग में 390 अंकों के साथ कुल 1185 अंकों से विश्व कीर्तिमान की बराबरी की।
- उन्होंने विश्व चैंपियनशिप की इस स्पर्धा में दूसरी बार विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले उन्होंने जर्मनी के सुहल में 2019 में खेले गए आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में 459.3 अंक हासिल कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था।
- उल्लेखनीय है कि खरगौन ज़िले की झिरनिया तहसील के गाँव रतनपुर में 3 फरवरी, 2001 को किसान परिवार में जन्मे ऐश्वर्य प्रताप सिंह वर्ष 2015 से मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी में प्रशिक्षणरत् है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अब तक तीन स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक देश को दिलाए हैं। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में ऐश्वर्य प्रताप ने 11 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदक अर्जित किये हैं।

एन.सी.पी.सी.आर. द्वारा 'बच्चों के लिये समर्पण' कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा 'बच्चों के लिये समर्पण' कार्यक्रम की शुरुआत मध्य प्रदेश के तीन ज़िलों- विदिशा, रायसेन और सीहोर से की गई।

प्रमुख बिंदु

- इसमें ऐसे बच्चों की वित्तीय सहायता की जाएगी, जिन्होंने कोरोना महामारी के कारण अपने माता-पिता में से किसी एक को या दोनों को खो दिया है।
- आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने बताया कि 'बच्चों के लिये समर्पण' कार्यक्रम का भविष्य में विस्तार किया जाएगा।
- वेदांतु इनोवेशन लिमिटेड द्वारा प्रदेश के तीन ज़िलों के आयोग द्वारा चिह्नित 83 बच्चों को निजी स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत बच्चों एवं उनके संरक्षकों के खातों में प्रति बच्चा प्रतिमाह दो हज़ार रुपए के मान से एक लाख 66 हज़ार रुपए की प्रथम किश्त अंतरित की गई।
- आयोग द्वारा कोविड-19 महामारी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए ऐसे सभी बच्चों का डाटा एकत्र किया गया है, जो असुरक्षित हो गए हैं, जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की ज़रूरत है तथा जिन्होंने अपने एकल अभिभावक या माता-पिता दोनों को कोविड-19 या मार्च 2020 के बाद किसी अन्य कारणों से खो दिया है। उन्हें लाभ पहुँचाने के लिये अशासकीय संगठनों को भी जोड़ा गया है।

'स्वामित्व योजना'

चर्चा में क्यों?

- 6 अक्तूबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'स्वामित्व योजना' के तहत मध्य प्रदेश के 19 ज़िलों के 3 हज़ार गाँव के 1 लाख 71 हज़ार ग्रामीणों को वर्चुअली भू-अधिकार अभिलेखों का वितरण किया।

प्रमुख बिंदु

- ज्ञातव्य है कि पंचायती राज मंत्रालय की इस केंद्रीय योजना को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल, 2021 को 9 राज्यों में योजना के पायलट चरण (2020-2021) के सफल समापन के बाद राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया था।
- इस योजना का लक्ष्य देश के गाँवों में लोगों को उनकी आवासीय भूमि का मालिकाना हक देना है। यह योजना ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मदद करेगी। यह योजना शहरी क्षेत्रों की तरह, ग्रामीणों की ओर से ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिये वित्तीय संसाधन के रूप में संपत्ति का उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त करेगी।
- इसका उद्देश्य नवीनतम सर्वेक्षण ड्रोन-प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय क्षेत्रों का सीमांकन करना है।

मध्य प्रदेश में बड़ी ग्राम पंचायतों में खुलेंगे उप-लोक सेवा केंद्र

चर्चा में क्यों?

- 7 अक्तूबर, 2021 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोक सेवा केंद्रों का विस्तार तहसील से आगे ग्राम पंचायत स्तर तक करने के लिये आगामी एक साल में पाँच हज़ार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में उप-लोक सेवा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- इन उप-लोक सेवा केंद्र के द्वारा नागरिकों को उनके द्वार पर सेवाएँ उपलब्ध करवाई जाएंगी। नागरिकों को खसरा की प्रति सिर्फ 10 रुपए प्रति पृष्ठ उपलब्ध करवाई जाएगी। यह सेवा 181 जनसेवा पर रजिस्टर्ड ह्वाट्सएप नंबर पर भी भेजने की सुविधा शुरू की जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चले जनकल्याण और सुराज अभियान के समापन दिवस पर यह घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 7 नये पोर्टल और 8 लोक सेवा केंद्र प्रारंभ किये।
- इनमें सामान्य प्रशासन, नगरीय विकास, योजना एवं सांख्यिकी, गृह और ऊर्जा विभाग के नवीन पोर्टल प्रारंभ किये गए। इन पोर्टल से नागरिकों को मिलने वाली जन सुविधाएँ बढ़ेंगी और उनके कार्य आसान होंगे। गृह विभाग के पोर्टल पर अब ई-एफआईआर हो सकेगी।

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं-
  - मध्य प्रदेश में 'ई-रुपी' की व्यवस्था को ई-वाउचर के रूप में लागू किया जाएगा। आयुष्मान भारत के अंतर्गत मरीजों की उपचार राशि एवं छात्रवृत्ति के भुगतान के लिये 'ई-रुपी' के माध्यम से सीधे हितग्राहियों को विशिष्ट प्रयोजन के उद्देश्य से कैश बेनिफिट ट्रांसफर किया जा सकेगा।
  - नवजात शिशु के माता-पिता को बच्चे के जन्म के समय ही जन्म प्रमाण-पत्र के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति प्रकरणों में जाति प्रमाण-पत्र भी प्रदान किये जाएंगे।
  - कुछ विशिष्ट नागरिक सेवाएँ, जैसे- वाहनों का फिटनेस, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, वाहन पंजीयन, दस्तावेजों की प्रमाणित नकल, सैप्टिक टैंक, सीवेज सफाई और वाटर टैंक के लिये सेवाएँ निजी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से भी प्रदान की जाएंगी।
  - नागरिक सेवाएँ, जैसे- आय, निवास प्रमाण-पत्र, खसरा/भू-अभिलेख, छात्रवृत्ति, पेंशन इत्यादि सेवाओं के लिये आवेदन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यथा व्हॉट्सएप/टेलीग्राम/कू ऐप पर प्राप्त करके नागरिकों को बिना शासकीय कार्यालय आए चेटबोट के माध्यम से संबंधित ऐप पर ही सेवा ऑनलाइन प्रदान की जाएगी।
  - समस्त सरकारी भर्तियों में चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन के संबंध में वर्तमान प्रचलित प्रक्रिया को सरल करते हुए केवल शपथ-पत्र के आधार पर नियुक्ति एवं ज्वाइनिंग दी जाएगी।
- इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आरोग्य संवर्द्धन कार्यक्रम की उपयोगिता और गंभीर कुपोषित बच्चों के समेकित पोषण से संबंधित पुस्तिका और मोटे अनाज़ों के महत्त्व और उनसे निर्मित व्यंजन के संबंध में पुस्तिका का विमोचन भी किया।

एकमुश्त समझौता योजना

चर्चा में क्यों?

- 7 अक्टूबर, 2021 को मध्य प्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ ने प्राथमिक गृह निर्माण संस्थाओं और उनके सदस्यों को बकाया ऋण की वसूली के लिये 'एकमुश्त समझौता योजना' लागू की है। योजना में दंड ब्याज में 100 फीसदी छूट देने का प्रावधान किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- एकमुश्त समझौता योजना के अंतर्गत 15 वर्ष से अधिक के ऋण प्रकरणों के 421 करोड़ 54 लाख रुपए के ऋण की वसूली हो सकेगी।
- वर्तमान में संघ द्वारा दी गई राशि पर ब्याज, दंड-ब्याज मिलाकर वर्तमान परिस्थितियों में ब्याज की दर अत्यधिक हो जाती है। इससे खाताधारकों पर बोझ बढ़ रहा है। साथ ही वसूली में भी आसानी नहीं होती और वैधानिक जटिलताओं की स्थिति बनती है।
- एकमुश्त समझौता योजना में बकायादार आवेदन देने के तिथि से 30 दिन की अवधि में कुल मांग की 25 प्रतिशत राशि जमा कर समझौते के पात्र हो जाएंगे। इसके बाद बकायादार को अगले छः माह में पूरी ऋण राशि जमा करना होगी।
- इस योजना का लाभ लेने के लिये ऋणी सदस्यों और क्षेत्रीय कार्यालय आवास संघ से संस्था निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त कर सकती है। ऋणी सदस्यों को संस्था के आवेदन पर क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा योजना में संपूर्ण बकाया राशि और योजना का लाभ देने के बाद शेष बकाया राशि की वसूली की जानकारी दी जाएगी।
- आवेदन पर अनुशंसा कर आवास संघ मुख्यालय भेजा जाएगा। आवास संघ मुख्यालय में आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन की समयावधि में प्रकरण का निराकरण कर दिया जाएगा। एकमुश्त समझौता की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रखी गई है।

पुलिस परिवार के बच्चों को रोज़गारोन्मुखी पाठ्यक्रम के लिये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस परिवार के बच्चों को रोज़गारोन्मुखी पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिये आईटीआई भोपाल पुलिस और आईटीएम विश्वविद्यालय ग्वालियर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।

प्रमुख बिंदु

- विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) अरुणा मोहन राव और विश्वविद्यालय के कुलपति एस.एस. भाकर ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।
- आईटीआई भोपाल के अपर पुलिस अधीक्षक सुमन गुर्जर ने बताया कि यह नया प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पारंपरिक पाठ्यक्रमों के अलावा पुलिस परिवार के बच्चों को रोज़गार के अवसर प्रदान करने में सहायक होगा।
- आईटीएम यूनिवर्सिटी के सहयोग से पुलिस परिवार के बच्चों के लिये फैशन डिज़ाइनिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, डिजिटल फोटोग्राफी, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डिजिटल कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज़्म एंड मास कम्युनिकेशन जैसी छह महीने की जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग शुरू की गई है। इन सभी के लिये आवंटित स्थान 30-30 होगा।
- इस आईटीआई परिसर में शासकीय नियमानुसार छात्रावास, पुस्तकालय, खेल का मैदान, जिम, अस्पताल/ओपीडी, मेस एवं छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है।

भोपाल के वैज्ञानिक ने देश का पहला प्लास्टिक फ्री सैनिटरी नैपकिन बनाया

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, भोपाल के वैज्ञानिक एवं पर्यावरण वैज्ञानिक डॉ. योगेंद्र कुमार सक्सेना ने देश का पहला सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री सैनिटरी नैपकिन तैयार किया है।

प्रमुख बिंदु

- यह नैपकिन बायोडिग्रेडेबल स्टार्च शीट, नॉनवोवेव कपड़ा, वूड पल्प शीट, सेप शीट और बैक साइड रिलीज पेपर टेप की सहायता से तैयार किया गया है। राग इनोवेशन पैड फैक्ट्री मैनपुरा ज़िला भिंड के विराग बोहरे ने इस इनोवेशन में उनकी मदद की।
- इस सेनिटरी नैपकिन को उपयोग के बाद बायो मेडिकल वेस्ट की ही तरह इंसीनरेटर में नष्ट करना होगा। इसे खुले में फेंकने, दफन करने या जला देने पर यह पर्यावरण के लिये वैसा नुकसानदायक नहीं होगा, जैसा मौजूदा नैपकिन होते हैं। दूसरे कई सेनिटरी नैपकिन में 90% सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग होता है।
- उल्लेखनीय है कि देश में 70% शहरी और 48% ग्रामीण महिलाएँ सेनिटरी नैपकिन का उपयोग करती हैं। इसमें से 24 प्रतिशत नैपकिन ही वैज्ञानिक रूप से निष्पादन के लिये इंसीनरेटर में जाते हैं, शेष 76 प्रतिशत में से 28 प्रतिशत सामान्य कचरे में पहुँच जाते हैं, 33 प्रतिशत ज़मीन में दफन कर दिये जाते हैं और 15% को खुले में जला दिया जाता है।
- एक नैपकिन को नष्ट होने में 500-800 साल लगते हैं। देश में कुछ लोगों ने बायोडिग्रेडेबल सेनिटरी नैपकिन बनाए हैं, लेकिन उनमें भी 20-25% प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है।
- उल्लेखनीय है कि डॉ. सक्सेना पहले भी गोकाष्ठ, गोबर के दीये और पीओपी की प्रतिमाओं को अमोनियम बाई कार्बोनेट में विसर्जन कर खाद बनाने जैसे नवाचार कर चुके हैं।

ग्वालियर में 'अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक न्यास' के गठन की स्वीकृति

चर्चा में क्यों?

- 12 अक्टूबर, 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता मे मंत्रिपरिषद की वर्चुअल बैठक में ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक के निर्माण और संस्कृति विभाग के अधीन स्वायत्त 'अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक न्यास' के गठन के लिये स्वीकृति दी गई।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- स्मारक न्यास के माध्यम से युवाओं और नौनिहालों में राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्र विकास के प्रति संवेदनशीलता तथा जागरूकता का प्रचार-प्रसार करने के लिये आवश्यक प्रयास किया जाएगा।
- वाजपेयी जी की भव्य प्रतिमा एवं दृश्य-श्रव्य माध्यमों से उनके जीवन चरित्र का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। प्रतिमा स्थल के आसपास सुव्यवस्थित जन-सुविधाएँ विकसित की जाएंगी। साथ ही उनके जीवन दर्शन से संबंधित गतिविधियों के संचालन के लिये कार्यशाला, सेमीनार, शोध, संगोष्ठी, व्याख्यान इत्यादि का आयोजन किया जाएगा।
- स्मारक परिसर में वाजपेयी जी एवं उनके जीवन दर्शन से संबंधित साहित्य का प्रकाशन तथा पुस्तकों की लाइब्रेरी/ई-लाइब्रेरी, सुशासन एवं नीति-निर्माण हेतु अध्ययन केंद्र की स्थापना तथा पर्यटन की दृष्टि से वाटर बॉडी, कैंटीन, पार्क आदि का विकास किया जाएगा।
- परिसर में राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्र विकास के प्रति संवेदनशीलता तथा जागरूकता का प्रचार-प्रसार करने के लिये फिल्मों का संग्रहण, दृश्य श्रव्य/मल्टीमीडिया, संग्रहालय, मुक्ताकाश मंच एवं ऑडिटोरियम आदि सुविधाओं का सृजन, उनकी बौद्धिक प्रखरता, साहित्यिक दृष्टिकोण और विशेष रूप से संसद में सशक्त उपस्थिति को प्रमुख आयाम के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा।
- न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भारत सरकार, राज्य सरकार, गैर-शासकीय संस्थाओं, संगठनों, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निकाय तथा व्यक्तियों से संपर्क समन्वय एवं सहयोग स्थापित कर क्रियान्वयन किया जाएगा।

अपशिष्ट प्रबंधन एवं निष्पादन के लिये एम.ओ.यू.

चर्चा में क्यों ?

- 12 अक्टूबर, 2021 को नगर निगम भोपाल और एनटीपीसी तथा भोपाल आरएनजी प्राइवेट लिमिटेड के मध्य अपशिष्ट प्रबंधन एवं निष्पादन किये जाने के लिये एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किये गए।

प्रमुख बिंदु

- यह एम.ओ.यू. 200 टन प्रतिदिन गीले कचरे से बायो सीएनजी प्लांट एवं 400 टन प्रतिदिन सूखे कचरे से टॉरीफाईड चारकोल प्लांट की स्थापना के लिये हुआ।
- ज्ञातव्य है कि वर्तमान में भोपाल शहर से लगभग 800 टन कचरा प्रतिदिन एकत्र होता है। इसके निष्पादन के लिये नगर निगम भोपाल द्वारा प्रति मीट्रिक टन 333 रुपए का व्यय किया जाता है। इस प्लांट के लगने से भोपाल आरएनजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भोपाल नगर निगम को 83 लाख रुपए की राशि प्रतिवर्ष रॉयल्टी के रूप में 20 वर्ष तक दी जाएगी एवं मार्केट रेट से 5 रुपए कम दर पर बायो सीएनजी प्रदान की जाएगी।
- प्लांट से उत्पन्न होने वाली बायो सीएनजी का उपयोग सिटी बसों में किया जाएगा। प्लांट की स्थापना पर 40 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है, जो पूर्णरूप से एजेंसी द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। एजेंसी द्वारा नगर निगम भोपाल से कचरा निष्पादन के लिये कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी।
- आदमपुर छावनी में 15 एकड़ भूमि के क्षेत्रफल में टॉरीफाईड चारकोल प्लांट की स्थापना 80 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से की जाएगी। यह राशि पूर्णरूप से एनटीपीसी द्वारा वहन किया जाएगा। उत्पादित टॉरीफाइड चारकोल का उपयोग एनटीपीसी के विद्युत संयंत्रों में किया जाएगा।
- 400 टन प्रतिदिन सूखे कचरे से टॉरीफाईड चारकोल प्लांट का निर्माण बिल्ट ऑन ऑपरेट मॉडल पर आधारित होगा। प्लांट की स्थापना एवं संचालन-संधारण कार्य एनटीपीसी द्वारा ही 25 वर्ष तक किया जाना है।

नोट :

भोपाल हाट में विंध्यावैली के दस स्वदेशी प्रोडक्ट लॉन्च

चर्चा में क्यों ?

- 13 अक्टूबर, 2021 को मध्य प्रदेश कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की प्रमुख सचिव स्मिता भारद्वाज ने भोपाल हाट में आयोजित चरखा खादी उत्सव में विंध्यावैली के दस स्वदेशी उत्पाद लॉन्च किये।

प्रमुख बिंदु

- 'आत्मनिर्भर भारत - आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश' संकल्पना के तहत खादी आयुर्वेद, ग्वालियर के हैंडमेड मिट्टी चारकोल साबुन, हैंडमेड केवड़ा साबुन, हैंडमेड मुल्तानी मिट्टी साबुन, हैंडमेड सेंडल वुड साबुन, अद्याति हर्ब्स एंड फूड प्रा. लि. जबलपुर के स्टीविया पाउडर, आज़ाद कुटीर उद्योग संस्थान, भोपाल की रूप मंज़ूरी, इम्यून प्राश, डायबिटीज पाउडर एवं खादी आयुर्वेद, ग्वालियर के केस्टर ऑयल, गुलाब जल एवं बॉडी ऑयल का शुभारंभ किया गया है।
- प्रमुख सचिव ने कहा विंध्यावैली मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अधीनस्थ एक बैनर है, जो स्वदेशी उत्पादों के निर्माण में लघु एवं कुटीर उद्यमों को सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करता है, वर्तमान समय में प्रदेश भर में इनकी इकाइयों में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश संकल्पना के तहत संचालन किया जा रहा है।
- उन्होंने बताया कि विंध्यावैली ब्रॉन्ड के अंतर्गत नवीन उत्पादों अगरबत्ती, स्टीविया पाउडर, इंडिगो पाउडर, रूप मंजरी, सतरीठा, इम्यून प्राश, डायबिटीज पाउडर, हैंडमेड साबुन की लॉन्चिग की गई एवं कबीरा रेडीमेड गारमेंट वस्त्रों की श्रृंखला में 98 नवीन लेडीज डिज़ाइनर वस्त्रों की बिक्री भी शुरू की गई।
- गौरतलब है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव एवं आत्म-निर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत खादी तथा ग्रामोद्योग के क्षेत्र में कार्यरत बुनकरों एवं अन्य कारीगरों को सतत् रोज़गार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा भोपाल हाट परिसर भोपाल में 9 अक्टूबर, 2021 से 20 अक्टूबर, 2021 तक चरखा खादी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 12 राज्यों की लगभग 110 खादी ग्रामोद्योग एवं हेंडीक्राफ्ट इकाइयाँ भाग ले रही हैं।

'गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान'

चर्चा में क्यों ?

- 13 अक्टूबर, 2021 को दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 'प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान' के शुभारंभ कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिंटो हॉल, भोपाल से वर्चुअली सम्मिलित हुए।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान दिल्ली से मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिये 'पी.एम. गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान' का शुभारंभ किया।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकास के इस महाअभियान में मध्य प्रदेश पूरी ताकत से जुटेगा। उन्होंने मध्य प्रदेश को तत्काल पी.एम. गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से जोड़ने का फैसला लिया।
- इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मिंटो हाल में राज्यस्तरीय 'कॉन्फ्रेंस ऑन मल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी' का शुभारंभ भी किया।
- ज्ञातव्य है कि गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो एकीकृत योजना और बुनियादी ढाँचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन के लिये रेल और सड़क मार्ग सहित 16 मंत्रालयों को एकसाथ लाएगा। मूलत: गति शक्ति में 200 प्रकार के डाटाबेस होंगे, जिसमें जीआईएस प्राणाली द्वारा भौतिक सुविधाओं, ज़िला प्रशासन कार्यालयों, रेल, सड़क और गैस लाइनों, स्वास्थ्य और पुलिस जैसी सुविधाओं के साथ जल निकायों, आरक्षित पार्कों तथा वनों जैसे संसाधनों की मैपिंग की जाएगी।
- इसके माध्यम से विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय एवं राज्य सरकारें बेहतर लॉजिस्टिक योजनाओं और कनेविटी से लाभान्वित हो सकेंगी।

नोट :

‘जायका’ का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

- 15 अक्तूबर, 2021 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल द्वारा संग्रहालय भ्रमण पर आने वाले दर्शकों की मांग पर भील जनजाति के पारंपरिक भोजन कार्यक्रम ‘जायका’ की शुरुआत की गई है।

प्रमुख बिंदु

- इस संबंध में निदेशक डॉ. प्रवीण कुमार मिश्र ने बताया कि पिछले दो दशकों में विश्व के तमाम बड़े वैज्ञानिकों ने अपने शोध से ये साबित किया है कि जनजातियों के प्राकृतिक आहार को अपनाने से पोषक तत्त्वों की कमी से होने वाले अनेक रोगों से निजात मिल सकती है।
- संग्रहालय की कैंटीन में प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को दोपहर 1 बजे से 4 बजे के मध्य प्रदेश की भील जनजाति का पारंपरिक भोजन मक्के की रोटी, बैगन का भर्ता, धनिया-लहसुन की चटनी, गुड़ आदि उपलब्ध रहते हैं।
- उल्लेखनीय है कि मक्के की रोटी का सेवन करने से शरीर को फाइबर प्राप्त होता है, जो पाचन संबंधी समस्याओं से राहत पाने में मदद करता है। यह शरीर में कॉलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। साथ ही फाइबर युक्त आहार से लंबे समय तक भूख नहीं लगती।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश

चर्चा में क्यों?

- 14 अक्तूबर, 2021 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश रवि विजयकुमार मलिमथ को सांदीपनि सभागार राजभवन में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि 16 सितंबर, 2021 को सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने देश के 8 राज्यों के मुख्य न्यायाधीश सहित कई अन्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की थी, जिनमें मध्य प्रदेश के तत्कालीन न्यायाधीश मोहम्मद रफीक को हिमाचल प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ को मध्य प्रदेश स्थानांतरित करने की सिफारिश शामिल थी।
- 25 मई, 1962 को जन्मे न्यायमूर्ति मलिमथ ने 28 जनवरी, 1987 को कर्नाटक हाईकोर्ट में वकालत शुरू की थी। इन्होंने बतौर अधिवक्ता संवैधानिक, सिविल, आपराधिक, श्रम और सेवा मामलों में महारत हासिल की। इन्हें 18 फरवरी, 2008 को कर्नाटक उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश और 17 फरवरी, 2010 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
- इन्होंने 5 मार्च, 2020 को उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद ग्रहण किया। 28 जुलाई, 2020 को इन्हें उत्तराखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके उपरांत हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर 7 जनवरी, 2021 को कार्यभार संभाला तथा 28 जून, 2021 को इन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ली।

लाडली लक्ष्मी उत्सव

चर्चा में क्यों?

- 14 अक्तूबर, 2021 को मध्य प्रदेश में राज्यस्तरीय ‘लाडली लक्ष्मी उत्सव’ का आयोजन प्रदेश की प्रत्येक आंगनबाड़ी एवं पंचायत भवन में वर्चुअल रूप से किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस कार्यक्रम में लगभग 40 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियों को वर्चुअली जोड़ा गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगल क्लिक के माध्यम से ‘लाडली लक्ष्मी उत्सव’ में प्रदेश की 21 हज़ार 550 लाडलियों के खातों में 5.99 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति का अंतरण किया।

- उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश सरकार ने बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंगानुपात में सुधार, बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से 1 अप्रैल, 2007 को 'लाडली लक्ष्मी योजना' लागू की थी।
- योजना के प्रारंभ से अब तक प्रदेश भर की 39.81 लाख बालिकाएँ लाडली लक्ष्मी योजना में पंजीकृत हो होकर लाभान्वित हो रही हैं।
- इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 'आत्मनिर्भर लाडली' को प्रारंभ करने की घोषणा की, जिससे प्रदेश की हर बेटी सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त हो सकेगी।
- इस योजना के तहत स्नातक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 2 साल की शिक्षा पूरी करने के बाद 20 हज़ार रुपए की राशि राज्य सरकार प्रदान करेगी। कॉलेज में दाखिला लेने वाली लाडली लक्ष्मी बेटियों को 25 हज़ार रुपए की राशि दी जाएगी। साथ ही, बेटियों के जन्म की संख्या के आधार पर लाडली लक्ष्मी फ्रेंडली ग्राम पंचायत/ग्राम घोषित करेंगे किये जाएंगे।
- हर सरकारी विद्यालय (सभी कन्या छात्रावासों सहित) में डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी केंद्र स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक लाडली लक्ष्मी को 18 वर्ष की आयु होने पर लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 'आत्मनिर्भर लाडली' को बेहतर बनाने के लिये आमजन से सुझाव लेकर योजना में बदलाव भी किये जाएंगे। प्रदेश के हर ज़िले में साल में एक दिन लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन भी किया जाएगा।

यूथ नेशनल सैलिंग चैंपियनशिप-2021

चर्चा में क्यों?

- 11 से 16 अक्तूबर, 2021 तक मलाड (मुंबई) में याचिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित यूथ नेशनल सैलिंग चैंपियनशिप-2021 में नेशनल सैलिंग स्कूल, भोपाल के खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 8 पदक जीते।

प्रमुख बिंदु

- विधित हो कि यह इवेंट एशियन गेम्स के चयन ट्रायल का दूसरा दौर है।
- इस चैंपियनशिप में रितिका दांगी ने लेजर 4.7 इवेंट में स्वर्ण पदक जबकि नेहा ठाकुर ने रजत पदक जीता।
- ऑप्टिमिस्ट ओवरऑल में एकलव्य बाथम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसी स्पर्धा में बालिका वर्ग में दिव्यांशी मिश्रा ने ओवरऑल तीसरे स्थान पर रहते हुए मध्य प्रदेश को रजत पदक दिलाया।
- 420 मिक्सड क्लास इवेंट में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक भी मध्य प्रदेश ने जीते। इस इवेंट में नैंसी राय और अनी राज सेंधव की जोड़ी ने स्वर्ण, विद्यांशी मिश्रा और मनीश शर्मा की जोड़ी ने रजत तथा पुष्कर बामरे व वंशिका सिंह परिहार की जोड़ी ने कांस्य पदक जीते।
- अंडर-12 ऑप्टीमिस्ट क्लास में शगुन झा ने मध्य प्रदेश को रजत पदक दिलाया।
- उल्लेखनीय है कि ये सभी खिलाड़ी राजधानी भोपाल की बड़ी झील स्थित नेशनल सैलिंग स्कूल में अर्जुन अवार्डी प्रशिक्षक जी.एल. यादव से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

एमएसएमई की नई पॉलिसी

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विभाग ने मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिये नई एमएसएमई विकास नीति बनाई है।

प्रमुख बिंदु

- इस नीति में प्रदेश में निवेश बढ़ाने के साथ ही स्थानीय युवाओं को रोज़गार मुहैया कराने के हर संभव प्रावधान किये गए हैं। मध्य प्रदेश कृषि उत्पादों में देश में काफी आगे है और इन उत्पादों का प्रदेश में ही प्रसंस्करण के लिये बनाई गई नीति में इन इकाइयों को अनेक सुविधाओं के साथ रियायतें दिये जाने की घोषणा की गई है।

- नीति में नवीन खाद्य प्रसंस्करण इकाई, जिसमें यंत्र-संयंत्र में 10 करोड़ रुपए से अधिक एवं 50 करोड़ रुपए तक का निवेश किया गया हो, को अनेक प्रकार की सहायता, सुविधाएँ प्रदत्त की जाएँगी।
- नीति के मुताबिक विद्युत खपत सहायता के अंतर्गत प्रचलित विद्युत टैरिफ में उच्च दाब उपभोक्ताओं को नवीन संयोजन प्राप्त करने पर एक रुपए प्रति यूनिट अथवा 20 प्रतिशत की छूट, जो भी कम हो, प्रदान की जाएगी। यह छूट खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिये उत्पादन, व्यावसायिक परिचालन की तिथि से 05 वर्ष तक की अवधि के लिये देय होगी।
- ऑफ-सीजन में कॉन्ट्रेक्ट डिमांड के 10 प्रतिशत अथवा वास्तविक रिकॉर्ड की गई डिमांड में से जो भी अधिक होगा, उसकी बिलिंग सामान्य टैरिफ पर की जाएगी, यह छूट संबंधित श्रेणी की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को देय होगी।
- इसी तरह मंडी शुल्क से छूट का प्रावधान भी नीति में है। ऐसे सभी पात्र खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश का अधिकतम 50 प्रतिशत या पाँच वर्ष की अवधि, इनमें से जो भी कम हो के लिये, मंडी शुल्क से छूट दी जाएगी। शुल्क से छूट की यह सुविधा उन इकाइयों को ही होगी, जो इस राज्य के कृषि उपजों का क्रय करेंगी।
- अधोसंरचना विकास सहायता के अंतर्गत मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने एवं अधोसंरचनाओं को बेहतर बनाने के लिये भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित मेगा फूड पार्क की स्थापना की योजना के मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार निजी क्षेत्र द्वारा मेगा फूड पार्क की स्थापना पर परियोजना लागत का 15 प्रतिशत या अधिकतम राशि 5 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- यह सहायता विकसित पार्क में न्यूनतम 10 इकाइयों की स्थापना पर देय होगी। यह सहायता टॉप-अप के रूप में देय होगी। स्टांप ड्यूटी की सहायता के तहत मेगा फूड पार्क की स्थापना के लिये प्रवर्तकों द्वारा स्पेशल परपज व्हीकल (SPV) को स्थानांतरित भूमि में प्रवर्तकों द्वारा भुगतान किये गए स्टांप ड्यूटी की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- इस विशेष पैकेज का लाभ प्राप्त करने वाली इकाइयाँ इस नीति के अंतर्गत घोषित अन्य शेष सुविधाएँ, जो समान प्रकार की न हों भी पात्रतानुसार प्राप्त कर सकेगी।

हाइब्रिड स्विचगियर मॉड्यूल तकनीक

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने प्रदेश में पहली बार इंदौर में ट्रांसमिशन सिस्टम के विस्तार में हाइब्रिड स्विच गियर मॉड्यूल सिस्टम का उपयोग किया है। जबलपुर मुख्यालय स्थित शक्ति भवन में पदस्थ कार्यपालन अभियंता एमडी पालंदे एवं मनीष खरे ने मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के सिस्टम के अनुरूप इस मॉड्यूल प्रणाली को विकसित और क्रियान्वित किया है।

प्रमुख बिंदु

- इस तकनीक का उपयोग इंदौर ईस्ट स्थित 220 केवी सब स्टेशन बिचोली में ट्रांसमिशन कंपनी ने 50 एमवीए क्षमता का एक नये स्थापित ट्रांसफार्मर में किया है।
- इसमें ट्रांसफार्मर से सप्लाई लेने वाले सिस्टम को 33 केवी वोल्टेज लेवल पर अंडरग्राउंड इंसुलेटेड केबल का उपयोग कर जोड़ा गया। मध्य प्रदेश में पहली बार 33 केवी के मेन सिस्टम के लिये इस तरह की उच्च क्षमता की इंसुलेटेड केबल का उपयोग किया गया है।
- इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन सहित घनी आबादी के शहरों में पहले से स्थापित अति उच्च दाब सब स्टेशनों में जगह की कमी के कारण विस्तार में कुछ समस्याएँ आ रही थीं, इन्हें दूर करने तथा विद्युत की बढ़ती मांग की आपूर्ति के लिये मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने हाइब्रिड स्विच गियर मॉड्यूल तकनीक के रूप में प्रदेश के ट्रांसमिशन सिस्टम में इस नए विकल्प को अपनाने का निर्णय लिया।
- प्रबंध संचालक सुनील तिवारी ने बताया कि विद्युत सब स्टेशनों में उपयोग की जाने वाली यह एक ऐसी मॉड्यूलर और कंपैक्ट डिजाइन सिस्टम है, जिसके एक मॉडल में कई अलग-अलग कार्य शामिल हैं।
- सब स्टेशनों के निर्माण और विस्तारीकरण के लिये यह मॉडल लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता पर आधारित है। हाइब्रिड मॉडल का उपयोग किसी भी पारंपरिक सब स्टेशन में विस्तार या प्रतिस्थापन के लिये किया जा सकता है।

- इसमें एयर इंसुलेटेड स्विच गियर और अत्याधिक विद्युत प्रतिरोधक क्षमता वाली सल्फर हेक्साफ्लोराइड आधारित गैस स्विचगियर की तकनीक वाले उपकरणों को एक ही मॉडल में उपयोग में लाया जाता है।
- यह हाइब्रिड तकनीक सब स्टेशनों में उपयोग होने वाली जगह में 50% तक की कमी लाता है तथा नई स्थापना या विस्तारीकरण के लिये यह एक भरोसेमंद और लागत प्रभावी समाधान है।

राष्ट्रीय मेरिट पुरस्कार 2018

चर्चा में क्यों?

- 18 अक्तूबर, 2021 को केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा जारी विभिन्न श्रेणी के राष्ट्रीय पुरस्कारों की सूची में मध्य प्रदेश की महिला शिल्पकार रशीदा-बी अब्दुल कादर खत्री का राष्ट्रीय मेरिट पुरस्कार वर्ष 2018 के लिये चयन किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- शिल्पकार रशीदा-बी खत्री को यह पुरस्कार चादर पर 'बाघ प्रिंट' की बारीक कारीगरी के लिये प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बाघ प्रिंटिंग में प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल कर आकर्षक लुक प्रदान किया है।
- ज्ञातव्य है कि रशीदा-बी खत्री को मध्य प्रदेश के धार ज़िले के ग्राम बाग में की जाने वाली बाघ प्रिंट ठप्पा छपाई कला में महारत हासिल है। वे एकमात्र महिला शिल्पकार हैं, जिन्हें इससे पूर्व भी वर्ष 2012 एवं 2014 में दो राज्यस्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- रशीदा-बी खत्री बाघ प्रिंट के लिये दुनिया भर में जाने-माने वाले मशहूर मास्टर शिल्पकार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय यूनेस्को पुरस्कार विजेता स्व. अब्दुल कादर खत्री की पत्नी हैं। वर्ष 2019 में इनके पति के निधन के बाद इन्होंने अपने पुत्र आरीफ मोहम्मद, हामीद एवं मो. अली के साथ मिलकर बाघ प्रिंट शिल्प को बढ़ावा देने का जिम्मा उठाया।

विद्युत दरों पर सब्सिडी

चर्चा में क्यों?

- 19 अक्तूबर, 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की वर्चुअल बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत दरों में 20 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया।

प्रमुख बिंदु

- घरेलू उपभोक्ताओं के लिये लागू योजना में 150 यूनिट तक की मासिक खपत पर प्रथम 100 यूनिट तक अधिकतम 100 रुपए का देयक दिये जाने और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बी.पी.एल. घरेलू उपभोक्ता, जिनकी मासिक खपत 30 यूनिट है, से मात्र 25 रुपए प्रति माह के मान से 4 माह में 100 रुपए लिये जाने का प्रावधान इस वर्ष भी रखा गया है।
- इसके साथ ही गृह ज्योति योजना में 4981.69 करोड़ रुपए की सब्सिडी स्वीकृत की गई है।
- कृषि उपभोक्ता श्रेणी को भी विद्युत दरों में राहत प्रदान करने का निर्णय लिया है। 10 हॉर्सपॉवर तक की क्षमता के मीटर रहित स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता को 750 रुपए प्रति हॉर्सपॉवर प्रति वर्ष की फ्लैट दर देय होगी। शेष राशि राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में देय होगी। इसके लिये राज्य सरकार द्वारा वितरण कंपनियों को 9876 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस निर्णय से मध्य प्रदेश के लगभग 21 लाख 75 हज़ार कृषि पंप उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।
- 10 हॉर्सपॉवर से अधिक की क्षमता के मीटररहित स्थाई कृषि पंप उपभोक्ता से 1500 रुपए प्रति हॉर्सपॉवर प्रति वर्ष की फ्लैट दर देय होगी। शेष राशि राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में वितरण कंपनियों को देय होगी। इसके लिये 644 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इससे प्रदेश के लगभग 50 हज़ार कृषि पंप उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।
- मीटरयुक्त स्थाई और अस्थाई कृषि पंप संयोजनों पर ऊर्जा प्रभार, ईंधन प्रभार एवं नियत प्रभार में छूट दी जाएगी। छूट राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में कंपनियों को किया जाएगा। इसके लिये 350 करोड़ रुपए की राशि देय होगी एवं इससे लगभग 2 लाख अस्थायी एवं 20 हज़ार मीटरयुक्त स्थाई कृषि पंप उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।

नोट :

- एक हेक्टेयर तक की भूमि वाले 5 हॉर्सपॉवर तक के अनुसूचित जाति और जनजाति के कृषि उपभोक्ताओं को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय की जाएगी। देयक की संपूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में देय होगी एवं इससे लगभग 9 लाख 25 हज़ार कृषि पंप उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। इसके लिये राज्य शासन द्वारा 4,733 करोड़ रुपए की राशि सब्सिडी के रूप में वितरण कंपनियों को दी जाएगी।
- उच्च दाब उदवहन/समूह सिंचाई उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार तथा वार्षिक न्यूनतम प्रभार में छूट दी जाएगी। छूट राशि राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में वहन की जाएगी। इसके लिये 90 करोड़ रुपए की राशि सब्सिडी के रूप में देय होगी।
- मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गए निर्णय से प्रदेश के कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को विद्युत देयक में 15,722.87 करोड़ रुपए की वार्षिक राहत प्राप्त होगी।

‘मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार’ योजना

चर्चा में क्यों?

- 19 अक्तूबर, 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा गरीब जनजाति परिवारों की सुविधा के लिये प्रदेश के आदिवासी विकासखंडों की उचित मूल्य दुकानों के आश्रित ग्रामों के पात्र परिवारों को उनके ही ग्राम से राशन सामग्री वितरण की योजना ‘मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार’ लागू करने का निर्णय लिया गया।

प्रमुख बिंदु

- यह योजना उप-चुनाव निर्वाचन आचार संहिता के ज़िलों को छोड़कर शेष ज़िलों के आदिवासी विकासखंडों में नवंबर, 2021 से लागू की जाएगी। योजना में 16 ज़िलों के 74 विकासखंड में 7,511 ग्राम के जनजातीय परिवार लाभान्वित होंगे।
- मुख्यालय स्थित गाँव को छोड़कर दुकान से संलग्न अन्य ग्रामों में वाहन के माध्यम से राशन सामग्री का वितरण किया जाएगा।
- ज़िला कलेक्टर द्वारा ग्राम में वितरण के लिये प्रत्येक माह के दिवस निर्धारित किये जाएंगे। एक वाहन द्वारा एक माह में औसतन 22 से 25 दिवस (अवकाश छोड़कर) 220 से 440 क्विंटल खाद्य सामग्री का वितरण किया जाएगा।
- खाद्यान्न परिवहन में अनुमानित 472 वाहन उपयोग किये जाएंगे। एक मीट्रिक टन वाले वाहन पर 24 हज़ार रुपए प्रतिमाह और 2 मीट्रिक टन वाले वाहन पर 31 हज़ार रुपए प्रतिमाह की दर से सालाना व्यय 14 करोड़ 7 लाख रुपए अनुमानित है।
- वाहन में खाद्यान्न लोड करते समय उसकी गुणवत्ता का परीक्षण किया जाएगा। वाहन में सामग्री तोलने के लिये इलेक्ट्रॉनिक तोल काँटा, माईक, स्पीकर, पी.ओ.एस. मशीन रखने, बैठने एवं खाद्यान्न सुरक्षित रखने की सभी व्यवस्थाएँ होंगी। वाहनों की व्यवस्था के लिये परिवहनकर्त्ताओं के साथ ज़िला स्तर पर अनुबंध किया जाएगा।
- परिवहनकर्त्ता उसी क्षेत्र के ग्रामों के निवासी होंगे। उनकी उम्र 21 से 45 वर्ष के बीच होगी तथा वे अनुसूचित जनजाति वर्ग से होंगे। परिवहनकर्त्ताओं को प्रतिमाह निर्धारित व्यय का भुगतान किया जाएगा।
- परिवहनकर्त्ता को वाहन क्रय के लिये ऋण राशि पर मार्जिन मनी प्रदान की जाएगी। एक मीट्रिक टन क्षमता वाले वाहन के लिये 2 लाख रुपए और 2 मीट्रिक टन या अधिक क्षमता वाले वाहन के लिये 3 लाख रुपए की मार्जिन मनी का भुगतान किया जाएगा। मार्जिन मनी की एकमुश्त राशि 9 करोड़ 69 लाख रुपए का भुगतान जनजातीय कार्य विभाग द्वारा किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर उचित मूल्य की दुकान संचालित करने का प्रावधान होने से दुकान के मुख्यालय ग्राम को छोड़कर शेष आश्रित ग्रामों के पात्र परिवारों को परिवहन के सुगम साधन न होने के कारण प्रतिमाह लगभग 5 किमी. दूरी तय कर 23 से 37 किग्रा. वजन की सामग्री सिर पर रखकर ले जानी पड़ती है।
- दिव्यांग, वृद्ध और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति को दुकान से राशन सामग्री प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न होती है एवं गरीब परिवारों को मज़दूरी का नुकसान भी होता है। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मंत्रिपरिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया है।
- योजना से हितग्राही की मज़दूरी एवं श्रम की बचत, पात्र परिवारों को निवास के ग्राम में राशन सामग्री का प्रदाय और समय पर राशन सामग्री का वितरण हो सकेगा।

'खादी शो'

चर्चा में क्यों?

- 19 अक्तूबर, 2021 को मध्य प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा हाट परिसर, भोपाल में चरखा खादी उत्सव में खादी वस्त्रों के डिज़ाइनर गारमेंट्स के प्रत्यक्ष प्रदर्शन 'खादी शो' का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- युवाओं के बीच खादी के कपड़ों के प्रति रुझान बढ़ाने तथा खादी के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से 'खादी शो' का आयोजन किया गया। इसमें मॉडल्स ने कबीरा खादी ब्रांड के विभिन्न परिधानों को पेश किया।
- भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' पर राष्ट्रपिता गांधीजी की परिकल्पना के अनुरूप खादी वस्त्रों के दैनिक जीवन में उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिये भी इस शो का आयोजन किया गया था।
- खादी परिधान प्रदर्शन में सभी उम्र वर्ग के गारमेंट्स एवं विभिन्न प्रकार की डिज़ाइनर ड्रेसों का प्रदर्शन किया गया। इन ड्रेसों को बोर्ड से संबद्ध डिज़ाइनरों द्वारा आकर्षक एवं वर्तमान प्रचलन के अनुरूप नवीनतम डिज़ाइन में तैयार किया गया।
- खादी कुर्ता, पायजामा, जाकेट, शर्ट, शेरवानी, कोट, लेडीज कुर्ता, ट्राउजर, प्लाजो, पैंट, जाकेट, साड़ियाँ और अनारकली कुर्ते इत्यादि विभिन्न मॉडलों द्वारा प्रदर्शित किये गए।
- इन डिज़ाइनर खादी वस्त्रों में ट्रेडिशनल, ब्लॉक, बाग, दाबू, बुटीक एवं वर्तमान में प्रचलित डिजिटल प्रिंट, मध्य प्रदेश के फ्लावर एवं फॉरेस्ट पर आधारित प्रिंट के प्रिंटेड गारमेंट्स शामिल थे।

'जीव दया पुरस्कार'

चर्चा में क्यों?

- 20 अक्तूबर, 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित आचार्य विद्यासागर जीवदया गोसेवा सम्मान योजना के तहत गो-संरक्षण और गो सेवा के क्षेत्र में वर्ष 2018-19 तथा वर्ष 2019-20 में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थागत श्रेणी के गोशालाओं को 'जीव दया पुरस्कार' प्रदान किये।

प्रमुख बिंदु

- इस समारोह में गो-संरक्षण एवं गो सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिये वर्ष 2018-19 का संस्थागत श्रेणी का प्रथम पुरस्कार आचार्य विद्यासागर गो-संवर्द्धन केंद्र लेहरदा ज़िला सागर को, तृतीय पुरस्कार दयोदय पशु सेवा केंद्र, अशोक नगर को प्रदान किया गया।
- गोपाल गोशाला कचनारिया (ज़िला उज्जैन), राज राजेश्वरी गोशाला गोटेगांव (ज़िला नरसिंहपुर), गोवंश रक्षण समिति वारासिवनी (ज़िला बालाघाट) एवं त्रिवेणी गोशाला झगड़िया (ज़िला बैतूल) को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया।
- गोसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिये वर्ष 2018-19 में व्यक्तिगत श्रेणी का प्रथम पुरस्कार सागर के सूरज सोनी (गोपुत्र), द्वितीय पुरस्कार रीवा के एस.के. उपाध्याय एवं तृतीय पुरस्कार पन्ना के ज्ञानचंद जैन को प्रदान किया गया।
- वर्ष 2019-20 में गो संरक्षण और गोसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिये दिये गए पुरस्कारों में संस्थागत श्रेणी में प्रथम पुरस्कार बाहुबली जीव रक्षा संस्थान मेघासिवनी (ज़िला छिंदवाड़ा) एवं द्वितीय पुरस्कार श्रीराम गो संवर्द्धन गोशाला बिरकुनिया (ज़िला सिंगरौली) को प्रदान किया गया।
- शीतला माता गोसेवा समिति (ज़िला उज्जैन), श्रीगणेश गोशाला (ज़िला आगरमालवा) एवं श्रीमद्भागवत गोशाला कनाडिया (ज़िला इंदौर) को इस श्रेणी का सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया।
- गो संरक्षण और गोसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिये वर्ष 2019-20 के व्यक्तिगत श्रेणी के पुरस्कारों में ग्वालियर के स्वामी ऋषभ देवानंद जी को प्रथम, दमोह के पवन राजपूत हटा को द्वितीय तथा मंडला की डॉ. श्वेता सिंह मरावी को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

- आचार्य विद्यासागर जीवदया गोसेवा सम्मान योजना के तहत गो संरक्षण और गोसेवा के उत्कृष्ट कार्यों के लिये संस्थागत श्रेणी के प्रथम पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 3 लाख रुपए, तृतीय पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपए तथा सांत्वना पुरस्कार के रूप में प्रत्येक को 50-50 हज़ार रुपए की राशि प्रदान की जाती है।
- इसी तरह व्यक्तिगत श्रेणी में प्रथम पुरस्कार के रूप में एक लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 50 हज़ार रुपए एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में 20 हज़ार रुपए की राशि एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

सोन चिरैया आजीविका उत्सव, 2021 का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

- 22 अक्तूबर, 2021 को मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने शिवाजी नगर भोपाल में महिला हाट-बाज़ार में राज्यस्तरीय 'सोन चिरैया आजीविका उत्सव, 2021' का शुभारंभ किया। यह आजीविका उत्सव 31 अक्तूबर, 2021 तक चलेगा।

प्रमुख बिंदु

- नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि 'दीन दयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन' के अंतर्गत गठित स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को अब सोन चिरैया ब्रांड के नाम से जाना जाएगा। स्व-सहायता समूहों के उत्पादों को सोन चिरैया ब्रांड के नाम से प्रदेश और देश में नई पहचान मिलेगी।
- इस राज्यस्तरीय उत्सव में प्रदेश के 24 नगरीय निकायों के स्व-सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों, जैसे- सज़ावटी सामान, जरदोजी की वस्तुएँ, ऑर्गेनिक उत्पाद, जूट के उत्पाद, ज्वैलरी, गिफ्ट आइटम, अगरबत्ती, अचार, बड़ी-पापड़, मसाले और खिलौने आदि का प्रदर्शन एवं विक्रय किया जा रहा है।
- इसके साथ ही उत्सव में महिलाओं द्वारा रंगोली, चित्रकला, मेहंदी, गायन आदि कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। उत्सव में स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा तैयार किये गए स्वच्छ एवं स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ विक्रय के लिये उपलब्ध हैं।
- नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने कहा कि स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों के विक्रय के लिये स्थान उपलब्ध कराने हेतु सभी शहरों में हाट-बाज़ार बनाए जाएंगे।
- उल्लेखनीय है कि अभी मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में 35 हज़ार स्व-सहायता समूह हैं, जिनमें 3 लाख 50 हज़ार महिलाएँ जुड़ी हुई हैं।

डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स कमेटी

चर्चा में क्यों?

- 22 अक्तूबर, 2021 को विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सुधारों से जुड़े परिणाम आधारित वितरण क्षेत्र योजना के लिये मध्य प्रदेश राज्य शासन ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की अध्यक्षता में डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स कमिटी का गठन किया है।

प्रमुख बिंदु

- प्रबंध संचालक एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को समिति का संयोजक बनाया गया है। समिति में अपर मुख्य सचिव पर्यावरण, प्रमुख सचिव वित्त, वन, ऊर्जा, राजस्व, पंचायत तथा नगरीय विकास एवं आवास सदस्य बनाए गए हैं।
- यह समिति राज्य स्तर पर योजना की प्रगति की समीक्षा करेगी। साथ ही, मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के लिये कार्ययोजना संबंधी अनुशंसा करेगी।
- भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी के अनुमोदन के लिये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर अनुशंसा प्रस्तुत करेगी। समिति परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के साथ ही गुणवत्ता की समीक्षा भी करेगी।

नोट :

शासकीय सेवकों के डी.ए. में 8% की वृद्धि

चर्चा में क्यों?

- 22 अक्तूबर, 2021 को मध्य प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने शासकीय सेवकों तथा स्थाईकर्मी को देय महँगाई भत्ते की दर में अक्तूबर 2021 से 8 प्रतिशत वृद्धि के आदेश जारी कर दिये हैं।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि कर्मचारियों को जनवरी 2019 से सातवें वेतनमान में 12% की दर से महँगाई भत्ता दिया जा रहा था। 21 अक्तूबर, 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महँगाई भत्ता दर में 8% की वृद्धि की घोषणा की थी। इस प्रकार सातवें वेतनमान के अनुसार, अब 20 प्रतिशत महँगाई भत्ता देय होगा।
- महँगाई भत्ते में वृद्धि करते हुए वित्त विभाग ने महँगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि महँगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप मंर नहीं माना जाएगा।
- इसके अतिरिक्त ऐसे सभी शासकीय सेवक, जो जुलाई 2020 या जनवरी 2021 की वार्षिक वेतन वृद्धि का काल्पनिक रूप से पात्रता है, उन्हें जुलाई 2020 से 1 जनवरी, 2021 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि के परिणामस्वरूप देय एरियर्स का भुगतान दो बराबर किश्तों में किया जाएगा। पहली किश्त (50%) का भुगतान नवंबर 2021 में और दूसरी किश्त (50%) का भुगतान मार्च 2022 में होगा।
- 1 मार्च, 2022 के पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके या होने जा रहे शासकीय सेवकों को एरियर्स की देय राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा।

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन लॉजिस्टिक्स

चर्चा में क्यों?

- 22 अक्तूबर, 2021 को मध्य प्रदेश में पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन लॉजिस्टिक्स की स्थापना हेतु देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर और भारत सरकार की स्वायत्त संस्था लॉजिस्टिक्स सेंटर काउंसिल के मध्य दो 'मेमोरंडम ऑफ एग्रीमेंट' पर हस्ताक्षर हुए हैं।

प्रमुख बिंदु

- यह सेंटर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा। 'लॉजिस्टिक सेक्टर स्किल काउंसिल' की हर राज्य में एक सेंटर देने की योजना है।
- उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में लॉजिस्टिक के कोर्स शुरू होने से प्रदेश के युवाओं के लिये रोज़गार के नए अवसर उपलब्ध होंगे।
- भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश केंद्र में स्थित होने के कारण औद्योगिक दृष्टिकोण से भी यह प्रयास उद्योगों को जोड़ने में सफल होगा। उन्होंने कहा कि यह सेंटर देश में पहली बार खुलने जा रहा है।
- इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में स्थापित होने वाले पहले 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन लॉजिस्टिक' में बी.ई. एवं बी.टेक. के अंतिम वर्ष में लॉजिस्टिक्स में स्पेशलाइजेशन (60 सीट) एवं इंडस्ट्री अप्रेंटीशिप प्रोग्राम तथा लॉजिस्टिक एवं डाटा साइंस में दो वर्षीय एम.एस. प्रोग्राम (30 सीट) लॉजिस्टिक सेक्टर काउंसिल की सहभागिता से प्रारंभ होगा।
- विश्वविद्यालय में लगभग में पाँच हज़ार युवाओं को 'लॉजिस्टिक्स स्किल डेवलपमेंट' की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिये औद्योगिक क्षेत्र के विशेषज्ञों को बुलाया जाएगा।

नोट :

प्रथम हॉकी इंडिया जूनियर बालक इंटर अकादमी नेशनल हॉकी चैंपियनशिप, 2021

चर्चा में क्यों ?

- 27 अक्तूबर, 2021 को मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम हॉकी इंडिया जूनियर बालक इंटर अकादमी नेशनल हॉकी चैंपियनशिप, 2021 के खिताब पर कब्ज़ा जमा लिया है।

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी ने फाइनल मुकाबले में राजा करण हॉकी अकादमी को 3-1 से हराकर लगातार दूसरा खिताब जीता। इससे पहले मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी ने प्रथम हॉकी इंडिया सब-जूनियर बालक इंटर अकादमी नेशनल हॉकी चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था।
- चैंपियनशिप में तीसरे स्थान के मुकाबले में नामधारी इलेवन ने राउंडग्लास पंजाब हॉकी अकादमी को 6-4 से पराजित किया।
- विजेताओं को खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया और पँश्री पुलेला गोपीचंद ने पुरस्कार वितरित किये। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी के सब-जूनियर एवं जूनियर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिये दोनों टीम के प्रत्येक सदस्य को 15 हज़ार रुपए एवं 20 हज़ार रुपए के चेक प्रदान किये।
- हॉकी इंडिया एवं खेल और युवा कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस चैंपियनशिप के मुकाबले मेजर ध्यानचंद स्टेडियम की नवनिर्मित टर्फ पर खेले गए।

स्टैंडिंग कमेटी

चर्चा में क्यों ?

- 27 अक्तूबर, 2021 को सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग बी.एस. जामोद ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021-22 में पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिये ज़िलास्तर पर स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष कलेक्टर एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी होंगे। पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज़िला पंचायत और निर्वाचन से जुड़े अधिकारी, जिन्हें ज़िला निर्वाचन अधिकारी आवश्यक समझें, इसके सदस्य होंगे।
- ज़िलास्तर पर गठित कमेटी की बैठक निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के पूर्व (मतदान केंद्रों की सूची प्रकाशित होने के पूर्व) आयोजित की जाएगी।
- इसके अतिरिक्त कलेक्टर एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी महत्त्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा के लिये, जब भी चाहें स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित कर सकते हैं।

दुष्यंत कुमार स्मृति पांडुलिपि संग्रहालय द्वारा वार्षिक अलंकरण की घोषणा

चर्चा में क्यों ?

- 27 अक्तूबर, 2021 को दुष्यंत कुमार स्मृति पांडुलिपि संग्रहालय द्वारा वार्षिक अलंकरणों की घोषणा की गई। संग्रहालय के संरक्षक मनोज सिंह मीक और अशोक निर्मल ने इन स्मृति पुरस्कारों की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- संग्रहालय के निदेशक राजुरकर राज ने बताया कि मुरादाबाद के मशहूर गीतकार महेश्वर तिवारी को राष्ट्रीय दुष्यंत पुरस्कार से नवाज़ा जाएगा।

- राजुरकर राज ने बताया कि स्मृति सम्मान समारोह नवंबर के अंतिम सप्ताह में आयोजित होगा और राष्ट्रीय अलंकरण समारोह 'प्रणाम-2021' संग्रहालय के स्थापना दिवस 30 दिसंबर, 2021 को आयोजित किया जाएगा।
- पुरस्कार के लिये घोषित व्यक्तियों के नाम हैं-
  - सुदीर्घ साधना सम्मान (यतींद्रनाथ राही, भोपाल)
  - क्षेत्रीय भाषा सम्मान (पी.सी. लाल यादव, छत्तीसगढ़)
  - कमलेश्वर सम्मान (वरिष्ठ साहित्यकार लक्ष्मीनारायण पयोधी)
  - कन्हैयालाल नंदन सम्मान (बाल साहित्यकार उषा जायसवाल)
  - बालकवि बैरागी सम्मान (वरिष्ठ कवि मनोहर पटेरिया मधुर)
  - विट्ठल भाई पटेल सम्मान (पत्रकार और परोपकारी राजेश गाबा प्रिंस)
  - आर.एस. तिवारी सम्मान (शहडोल आयुक्त राजीव शर्मा (आईएएस))
  - राजेंद्र जोशी सम्मान (माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के संजीव गुप्ता)
  - डॉ. सुषमा तिवारी सम्मान (कवयित्री डॉ. मीनू पांडेय 'नयन')
  - डॉ. बाबूराव गुजरे सम्मान (लघुकथा केंद्र की कांता राय)
  - अखिलेश जैन सम्मान (सेंट्रल बैंक के संजय लांबा)
  - विजय शिरढोणकर सम्मान ('समागम' पत्रिका के संपादक मनोज कुमार)
  - बृजभूषण शर्मा सम्मान (लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्त्ता जया आर्य)

एम्स भोपाल और आईआईएसईआर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

चर्चा में क्यों?

- 28 अक्तूबर, 2021 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल और भारतीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISER), भोपाल ने नमूनों के विश्लेषण के लिये नैदानिक नमूनों और प्रौद्योगिकी को साझा कर जन-स्वास्थ्य, मेटाजेनोमिक्स, कैंसर, महामारी विज्ञान और उपचार के क्षेत्र में सहकारी अनुसंधान करने हेतु पाँच साल के लिये एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।

प्रमुख बिंदु

- यह समझौता ज्ञापन मध्य प्रदेश में अन्य अनुसंधान संस्थानों के साथ एक अनुवाद अनुसंधान क्लस्टर बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- दोनों संस्थानों के बीच अंत:विषय अनुसंधान से महत्त्वपूर्ण खोजें होंगी। दोनों संस्थान संयुक्त रूप से सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, फैकल्टी और स्टूडेंट एक्सचेंज का आयोजन करेंगे।

राष्ट्रीय सीनियर कैनो स्प्रिंट कयाकिंग-कैनोइंग चैंपियनशिप, 2021

चर्चा में क्यों?

- 24 से 27 अक्तूबर, 2021 तक हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में आयोजित 31वीं राष्ट्रीय सीनियर कैनो स्प्रिंट कयाकिंग-कैनोइंग चैंपियनशिप, 2021 में मध्य प्रदेश राज्य जल क्रीड़ा अकादमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 12 स्वर्ण, 12 रजत और 5 कांस्य पदक जीते।

प्रमुख बिंदु

- चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की महिला टीम ने ओवरऑल चैंपियनशिप जीती, जबकि पुरुष टीम ओवरऑल उपविजेता रही।
- मध्य प्रदेश राज्य जल क्रीड़ा अकादमी की कावेरी धीमर ने इस चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 मेडल अपने नाम किये।
- गौरतलब है कि सीहोर ज़िले के गाँव मंडी की रहने वाली कावेरी धीमर पिछले तीन साल से नेशनल चैंपियन हैं।

नोट :

मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना

चर्चा में क्यों ?

- 29 अक्तूबर, 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल कार्यक्रम के ज़रिये 'मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना' के तहत 7700 संबल हितग्राहियों के बैंक खातों में 170 करोड़ रुपए ट्रांसफर किये।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना वर्ष 2018 में प्रारंभ की गई राज्य सरकार की एक महत्त्वपूर्ण योजना है, जो प्रत्येक परिस्थिति में राज्य के लोगों को जीवन सुगमता एवं आजीविका हेतु सहायता प्रदान करती है।
- योजना के अंतर्गत दुर्घटना से मृत्यु, सामान्य मृत्यु एवं अंतिम संस्कार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है-
  - दुर्घटना से निधन होने पर 4 लाख रुपए
  - सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए
  - अंतिम संस्कार के लिये 5 हज़ार रुपए